श्री प्रेम चन्द गुप्ताः अगर है तो उसको implement क्यों नहीं किया जाता? श्रीमन्, जहां से मैं आता हूं, आज भी मैं वहां पर देखता हूं, जब हम वहां जाते हैं तो manual scavenging चल रही है। यह बहुत ही दुभार्ग्यपूर्ण स्थिति है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो राज्य information नहीं देते हैं या cooperate नहीं करते हैं, क्या उनके ऊपर किसी तरह की penalty का प्रावधान है या जो Municipal Committees हैं, उनके ऊपर criminal offence का कोई प्रावधान किया जा सकता है, ताकि इस कुप्रथा को खत्म किया जा सके?

श्री थावर चन्द गहलोतः सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारे यहां की व्यवस्था संघीय ढांचे की है। राज्य सरकार के अपने अधिकार हैं और जो 2013 का कानून बना है, उसमें राज्य सरकार को ही इसे implement करना है, राज्य सरकार को ही identify करना है और उनकी सूचना हमें देकर आर्थिक सहयोग की अपेक्षा करनी होती है और हम उनको वह सुविधा देते हैं।

मैं इस अवसर पर एक और जानकारी देना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सारे देश में स्वच्छता अभियान प्रारम्भ किया गया है और अभी तक जो गंदी लेट्रीन्स हुआ करती थीं या किसी के घर में लेट्रीन्स नहीं होती थीं, ऐसे घरों में 24 लाख से अधिक फ्लश लेट्रीन्स बनाकर देने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था पहले की गई होती, तो यह समस्या समाप्त हो जाती।

श्री तपन कुमार सेनः सर, इसमें एक बात है कि जो सेंट्रल एक्ट है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट उसे लागू नहीं करती है, तो उसके लिए कुछ प्रावधान होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Maybe a periodic report.

Promotion of clean urban transport in cities

*154. DR. PRABHAKAR KORE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government proposes to promote clean urban transport by building footpath, non-motorized transport, Bus Rapid Transit (BRT), etc. in cities;

(b) whether Government also proposes to promote the use of clean fuel, electric, hybrid buses and intelligent traffic system in cities; and

(c) if so, the details thereof and the categories of cities likely to be covered under the plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (RAO INDERJIT SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Yes, Sir. A green urban mobility scheme is being considered to promote urban mobility initiatives such as footpaths, cycle tracks, public bike sharing, bus rapid transit systems, intelligent transport systems, urban freight management and

innovative financing for public transport systems; and progressively shift to usages of hybrid/electric and non-fossil fuels for public transport. The scheme requires extensive stakeholders' consultations before firming up the details. The scheme tentatively proposes to cover all cities/towns with a population of 5 lakhs and above (Census 2011) and capital cities/towns of States/Union Territories.

DR. PRABHAKAR KORE: Most of the big cities in the country like Delhi, Mumbai, Pune, Bangalore, etc., are highly polluted with a high percentage of carbon emissions. If the Government is not controlling tier-II cities, then what is the plan to reduce pollution and carbon emissions in even the existing big cities? At the same time, what is the plan for upcoming cities having population of more than five lakh or ten lakh people? Are you planning for alternative transport so that carbon emissions can be reduced?

राव इंद्रजीत सिंहः चेयरमैन साहब, मैं माननीय सदस्य को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और इस सदन का ध्यान एक बड़े अहम मसले की तरफ आकर्षित किया है। जब से मोदी सरकार बनी है, पिछले ढाई-तीन वर्ष के दौरान कई अहम फैसले मिशन के तौर पर लिए गए हैं, जिसके अंदर स्वच्छ भारत है, स्मार्ट सिटीज़ है, AMRUT है, लेकिन यह एक मसला ऐसा था जिसके ऊपर अभी तक अमल नहीं किया जा सका था। आज इस प्रश्न का जवाब देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार इस बात के ऊपर आज के दिन इनके मुताबिक चिंतित है। एक नयी योजना जिसका नाम " Green Urban Transport " होगा, इसको सरकार बनाने जा रही है। यह अभी प्रस्तावित है और अभी यह अरबन डेवलपमेंट महकमे के अधीन ही है, अभी तक इसको कैबिनेट से approval नहीं मिला है, इसलिए यह अभी flexible है, लेकिन इस प्लान्ड मिशन के अंदर, यह जो सात साल का मिशन होगा, इसके अंदर urban mobility/green mobility के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जिसके अंदर infrastructure enabling bus systems बनेंगे यानी कि बस नहीं दी जाएगी, बल्कि बस के लिए सुविधा दी जाएगी, जैसे — BRT System बनाया जाएगा, उनके डिपोज़ बनाए जाएंगे, उनकी वर्कशॉप बनाई जाएगी। इन बसों को चलाने के लिए प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे उसके अंदर पैसे लगाकर safe बस चलाने की बात करें। इसी तरह से इसका एक दूसरा पहलू है — safe pedestrian pathways, cycling tracks, public bike sharing वगैरह इस योजना के अंदर है। तीसरा, इसका पहलू है, Integrating modes with physical and soft infrastructure जैसे कि कैशलेस पेमेंट के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसी के साथ-साथ urban freight management का भी इसके अंदर प्रावधान है। यह भी इसमें प्रावधान है कि urban freight management किस तरीके से किया जाए? जैसे-जैसे समय गुज़रेगा तो हम यह कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में sustainable vehicles and sustainable fuels इस्तेमाल किए जाएं और धीरे-धीरे internal combustion engine से we shift to electric-cum-hybrid vehicles for public transport and to non-fossil fuel for public transport system. सर, आज के दिन यह flexible है और rigidity इस के अंदर नहीं आयी है क्योंकि इसे कैबिनेट से अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, अगर कोई माननीय सदस्य इस विषय में कोई और सुझाव देना चाहें, तो हम उसे incorporate करने के लिए तैयार हैं।

डा. प्रभाकर कोरेः सर, दूसरे मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज में बहुत बुरा हाल है। am asking about the second line cities, जिनकी पॉपुलेशन अब 10-15 लाख हो गयी है। उनमें आप को BRT स्टार्ट करना पड़ेगा और दूसरी नयी-नयी technologies लाकर छोटी मेट्रो रेल स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा प्रोवीजन लाना चाहती है कि जो नई सिटीज बन रही हैं या जो सिटीज एक्सटेंड हो रही हैं, उनके लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? साथ ही जो existing बड़ी सिटीज हैं, जहां कि पॉल्यूशन ज्यादा है, जैसे कि Delhi, I think, is the biggest polluted city in this part of the world, इन्हें आप क्या सुविधा देने जा रहे हैं? आपकी इस संबंध में क्या प्लानिंग है? सर, कल जो समस्या आने वाली है, उसके बारे में हमें आज ही सॉल्यूशन ढूंढ़ना होगा। इस बारे में सरकार क्या सोच रही है?

राव इंद्रजीत सिंहः चेयरमैन सर, माननीय सदस्य की बात दुरुस्त है कि बड़ी सिटीज को पहले लिया जाना चाहिए और छोटी सिटीज का नंबर बाद में आएगा। सर, इस स्कीम के अंदर मौजूदा तौर पर 103 सिटीज ली गयी हैं। ये सिटीज वे हैं, जिन की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। इस के साथ-साथ जिन की जनसंख्या 5 लाख से कम है, लेकिन ये शहर किसी स्टेट की कैपिटल हैं, तो उन्हें भी इस स्कीम में शामिल किया गया है। इस तरह स्टेट कैपिटल्स cum 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को मिलाकर कुल 103 शहर आज के दिन identify किए गए हैं, इनके ऊपर यह स्कीम पहले चरण में लागू की जाएगी। सर, यह स्कीम 7 साल तक चलने की संभावना है। इस स्कीम के तहत इन 7 सालों में तकरीबन 70 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे और इन 70 हजार करोड़ रुपयों की फंडिग के बारे में मिनिस्ट्री के सामने यह प्रस्ताव है कि 10 फीसदी फंड अर्बन लोकल बॉडी भरेगी, स्टेट गवर्नमेंट 30 फीसदी भरेगी, जहां कि यह कैपिटल सिटी या शहर है और 30 फीसदी भारत सरकार अपनी तरफ से ग्रांट के तौर पर इस योजना के तहत देगी। अब जो बकाया 30 फीसदी रह जाता है, उसे किसी Multilateral Agency से लोन के तौर पर लेकर इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा।

डा. अनिल कुमार साहनीः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शहरों में पॉल्यूशन को रोकने के लिए आप hybrid electric व्हीकल्स चलवा रहे हैं, मगर नए-नए शहर जिनकी जनसंख्या 5-7 लाख है, आज वहां नए-नए उद्योग भी खुल रहे हैं, तो क्या धुआं रहित उद्योग खोलने की क्या आपकी कोई योजना है? महोदय, आज इन शहरों में मोटर साइकिल और गाड़ियों से बहुत प्रदूषण होता है और सब से ज्यादा प्रदूषण धुआं उद्योग से होता है। इन से निकलने वाले धुएं को रोकने और व्हीकल्स को hybrid बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं या आपके पास कोई कार्यक्रम है?

राव इंद्रजीत सिंहः सर, यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में सवाल है और इस के लिए इलैक्ट्रिक व्हीकल्स, सन की ऊर्जा से चलने वाले व्हीकल्स के बारे में हमने चर्चा की है और जैसा कि मैंने सदन के सामने कहा है, हम शुरुआत में बड़े शहरों को लेंगे। सर, चाहे जितना लंबा रास्ता हो, उस के लिए शुरुआत पहले कदम से ही होती है। इसलिए हमने पहले कदम के तौर पर 103 सिटीज ली हैं। उसके बाद हमारी योजना में यह भी है कि जब यह सुचारु रूप से चालू हो जाएगी, तो छोटे शहरों में भी इस चीज को extend करेंगे।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, in the reply, the hon. Minister says that a green urban mobility scheme is being considered to promote urban mobility initiatives such as footpaths, cycle tracks, public bike sharing, bus rapid transit system, etc. Here, I would like to say that Bus Rapid Transit System was introduced in the UPA Government. It was very successful and popular. Why is this not being started?

I would also like to know this. In the reply, the Minister has said that the scheme requires extensive stakeholders' consultations before firming up the details. I would like to know: When are you going to come up with this scheme? What is the actual time period? In the reply it is stated that the scheme tentatively proposes to cover all cities. That is a very welcome factor. But when are you going to introduce this green urban mobility scheme? It is a very welcome factor. I want to know the details.

RAO INDERJIT SINGH: Sir, the BRT System is being implemented in various cities. One city, in particular, Delhi has had to remove it because there was opposition to it but in other cities this BRT Scheme is being implemented and is doing a good job there. Nobody has complained about it there. It is part and parcel of the scheme that we have on the anvil. *vis-à-vis* the time when we are going to start implementation of the Green Urban Mobility Scheme, that has to get the stamp of approval from the Cabinet. Once the Cabinet approves it, then we will start.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, what is the time-limit? ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Ramakrishna. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)... No supplementaries on supplementaries. ...(*Interruptions*)...

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA: Sir, I wanted to commend the example of San Francisco city, which uses the same vehicle as a bus in certain stretches, as a tram in certain other stretches and as an underground metro in certain other stretches. This type of example can be followed in many medium cities, for instance, Srinagar, where one side is the Dal Lake and the other side is constructed and the roads are very, very narrow. You do not even have a public sector transport there. In such cities, I think, we can follow this example where you can use hybrid model of fuel and have the same vehicle operating in multiple forms in a seamless manner.

I just wanted to commend that example.

RAO INDERJIT SINGH: It is a good suggestion. We will consider it. But I have already said that we are already integrating roads with physical and soft infrastructure which means that all three types of systems like trams, subways, buses, all these things will be integrated through one common card. This is what is part of the plan.